

77

अधिसूचना

संख्या: 5/नि./अं.पदा.स्था. 25/06, 4624/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, सहकारिता विभाग के विहार सहकारी अंकेक्षक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शक्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं -

- | क्रमांक | पद का नाम | कोटि | वेतनमान |
|---------|----------------------------|--------------------------|------------|
| (i) | अंकेक्षक (सहयोग समितियाँ) | मूल कोटि | 4500-7000 |
| (ii) | वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी | प्रोन्नति का प्रथम चरण | 5500-9000 |
| (iii) | अनुमंडल अंकेक्षण पदाधिकारी | प्रोन्नति का द्वितीय चरण | 6500-10500 |

(5) आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की जा सकेगी।

(6) प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन हेतु पाठ्यक्रम एवं आप्तांक का विनिश्चय आयोग के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

5. परीक्ष्यमान अवधि - नियुक्ति के पश्चात् परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षों की होगी। उक्त अवधि में सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं होने पर परीक्ष्यमान अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी और विस्तारित परीक्ष्यमान अवधि में भी सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर वैसे कर्मी को सेवामुक्त किया जा सकेगा।

6. प्रशिक्षण - (1) संवर्ग के सदस्यों को परीक्ष्यमान अवधि में नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकेगी।

(2) संवर्ग के सदस्यों के लिए समय-समय पर अल्पावधि के रिक्रेशर की व्यवस्था भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

7. सम्पुष्टि - संवर्ग में नियुक्त सदस्य संतोषप्रद रूप से परीक्ष्यमान अवधि एवं आवश्यक प्रशिक्षण पूरा करने पर संवर्ग में सम्पुष्टि किये जा सकेंगे।

8. प्रोन्नति - (1) संवर्ग में सम्पुष्टि अंकेक्षक, सहयोग समितियाँ से, वरीय अंकेक्षक पदाधिकारी एवं वरीय अंकेक्षक पदाधिकारी से अनुनंद्ल अंकेक्षक पदाधिकारी के पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता के आधार पर विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जा सकेगी।

(2) एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रोन्नति के लिए राज्य सरकार (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा समय-समय पर निर्धारित कांजावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

9. प्रतिनियुक्ति - संवर्ग के सदस्यों को राज्य सरकार के पूर्णतः या अंशतः स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली सहकारी समितियों, निकाय या परियोजना में घिहित पदों के विरुद्ध भी प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा।

10. कठिनाई का निराकरण - इस नियमावली के किसी भी नियम को लागू करने में कठिनाई हो तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई का निराकरण समुचित आदेश से कर सकेगी।

11. इस नियमावली के नियमों की व्याख्या करने के लिए विभाग सक्षम होगा और आवश्यकतानुसार दत्त/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा सकेगा।

12. जिन विषयों या विन्दुओं का प्रावधान इस नियमावली में नहीं किये गए हैं, उसके संबंध में राज्य सरकार के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विजय कुमार शर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।

आपक : 5/नि./अ.पदा.स्था.-25/08, 4624

पटना, दिनांक : 04.8.08

प्रतिनिधि : अधीक्षक सचिवालय गुदणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 200 (दो सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।